"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः आश्विन 27, 1944
बुधवारः 19 अक्तूबर 2022

रक्षा मंत्री ने डेफएक्सपो 2022 के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र प्लस रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया

क्षेत्र में सभी के हित के लिए नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया

हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के संबंध में वर्तमान और उभरते खतरों से निपटने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता: श्री राजनाथ सिंह

"हम रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के शून्य-योग प्रतिमान की सदस्यता नहीं लेते हैं; हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जीत प्राप्त करना-जीत प्राप्त करना प्रतिमान में विश्वास करते हैं"

फरवरी 2021 में आयोजित 'हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन' की शानदार सफलता के बाद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफएक्सपो के दौरान आईओआर+ रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 40 देशों ने भाग लिया, जिसमें 22 मंत्रियों ने सम्मेलन को संबोधित किया, जिनमें से कुछ हाइब्रिड मोड में थे। व्यापक विषय 'हिंद महासागर में चुनौतियां, अवसर और सहयोग' था। इसने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की परिकल्पना (सागर) के अनुरूप आईओआर के भीतर रणनीतिक और वाणिज्यिक साझेदारी के साथ एक स्थिर और शांतिपूर्ण हिंद महासागर को बढ़ावा देने की दिशा में संवाद की सुविधा प्रदान की।

मुख्य भाषण देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संस्थागत और सहयोगपूर्ण वातावरण में संवाद को बढ़ावा देने की पहल बताया जो आईओआर में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस फोरम का नाम आईओआर+ रखा गया है क्योंकि इस कॉन्क्लेव का चिंतन साझा जिम्मेदारी और समृद्धि है। उन्होंने कहा, "हम एक बहु-संरेखित नीति में विश्वास करते हैं जिसे कई हितधारकों के साथ जुड़ाव के माध्यम से महसूस किया जाता है, ताकि सभी के सुझावों और चिंताओं पर चर्चा की जा सके और सभी के समृद्ध भविष्य की खोज की जा सके। भारत क्षेत्र में सभी के लाभ के लिए नियम आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ काम करने का इच्छुक है।"

रक्षा मंत्री ने सागर के प्रति प्रधानमंत्री की परिकल्पना को नई दिल्ली की हिंद महासागर नीति का विषय बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री का परिकल्पना को उद्धृत करते हुए कहा, "हिंद महासागर क्षेत्र के लिए हमारा दृष्टिकोण क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने और हमारे साझा समुद्री क्षेत्र में सभी के लाभ के लिए हमारी क्षमताओं का उपयोग करने में निहित है"।

श्री राजनाथ सिंह ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बयान 'अन्याय कहीं भी न्याय के लिए खतरा है' का हवाला देते हुए कहा कि यह उच्च कनेक्टिविटी और अन्योन्याश्रितता के इस युग में अत्यधिक प्रासंगिकता रखता है। उन्होने कहा कि जब किसी भी क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा होता है, तो पूरी दुनिया कई तरीकों से उसके प्रभाव को महसूस करती है। हाल ही में यूक्रेनी संघर्ष से पता चला है कि इसके प्रभाव सबसे कमजोर देशों के लिए ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसी तरह, असफल राज्य न केवल अपने क्षेत्र के लिए, बल्कि बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए भी एक चुनौती पैदा करते हैं, क्योंकि ये राज्य आतंकवाद, समुद्री डकैती और तस्करी की नर्सरी के रूप में कार्य कर सकते हैं। हमारा मानना है कि इस तरह के मंचों के माध्यम से हमारे साझेदार देशों को शामिल कर हम एक-दूसरे की चिंताओं को महसूस कर सकते हैं और इससे एक वैश्विक व्यवस्था बनाने में मदद मिलती है जो हम सभी के लिए फायदेमंद है।

रक्षा मंत्री ने आईओआर में सुरक्षा और स्थिरता के लिए वर्तमान और उभरते खतरों से निपटने की दिशा में सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहले ही अपने सक्रिय पांच 'एस' दृष्टिकोण में वैश्विक चिंताओं से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को रेखांकित किया है, जिसमें सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि शामिल हैं। श्री राजनाथ सिंह ने एक जिम्मेदार भूमिका निभाने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा में योगदान देने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "हमने आईओआर के विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर संगठनात्मक और संक्रियात्मक पहलुओं में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने जुड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं कि यह क्षेत्र निकट भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था के ड्राइविंग इंजन के रूप में अपना उचित स्थान हासिल करे।"

श्री राजनाथ सिंह ने आईओआर में समुद्री मार्गों के माध्यम से आतंकवाद के प्रसार, अवैध, बिना सूचना दिए और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने, समुद्री डकैती और क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि समुद्री मार्गों के माध्यम से भेजा जाने वाला, समर्थित या समन्वित आतंकवाद एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और भारत खतरे के प्रसार से लगातार बच रहा है। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती को बंद कर दिया गया है और इस खतरे को रोकने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहने चाहिए।

आईयूयू मछली पकड़ने के बारे में रक्षा मंत्री ने विभिन्न स्रोतों अर्थात उपग्रहों, रेडार, टोही विमानों या मानव आसूचना से एकत्र किए गए निगरानी डेटा के संकलन, मिलान और साझा करने के लिए एक बहु-राष्ट्रीय प्रयास का आह्वान किया। यह अनियमित या धमकी भरे व्यवहार वाले अभिनेताओं की पहचान करने में मदद करेगा, जिसका दृढ़ता से मुकाबला करना होगा।

श्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि भारत वैश्विक व्यवस्था की किसी भी पदानुक्रमित अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक श्रेष्ठता के बाहरी दिखावे को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली हर देश के पारस्परिक सम्मान और लाभ पर आधारित वैश्विक व्यवस्था में विश्वास करती है। "हम रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के शून्य-योग प्रतिमान की सदस्यता नहीं लेते हैं। बल्कि, हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जीत प्राप्त करना-जीत प्राप्त करना प्रतिमान में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, 'भारत आईओआर की शांति और स्थिरता की मांग करते हुए राष्ट्रों के बीच सहयोग और करीबी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए हमारे साझेदार देशों की सरकार, व्यापार और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों के साथ काम करने के लिए तत्पर है।

रक्षा मंत्री ने समुद्री संसाधनों के सतत नियंत्रित उपयोग को 21वीं सदी में आईओआर के देशों की वृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगी प्रयास का आह्वान किया कि हिंद महासागर का समुद्री विस्तार शांतिपूर्ण हो और क्षेत्रीय तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम रूप से उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा, "हमने नियम आधारित व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया है और हिंद महासागर को शांति एवं स्थिरता के क्षेत्र के रूप में पोषित करने की आवश्यकता पर जोर देना जारी रखा है। हम दोहराना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण व्यापार और ऊर्जा जलमार्ग को स्थिर रखने के लिए प्रभुत्व के बजाय परस्पर निर्भरता ही एकमात्र तरीका है। दुनिया के आधे कंटेनर शिपमेंट, इसके थोक कार्गो ट्रैफिक का एक तिहाई और तेल शिपमेंट का दो तिहाई हिस्सा इसके पार ले जाया जा रहा है, आईओआर स्पष्ट रूप से हमारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है।"

श्री राजनाथ सिंह ने पोतों, समुद्री विमानों, तटीय रेडार और अन्य निगरानी प्रणालियों, प्रशिक्षण, भारतीय शिपयार्डों तक पहुंच और समान क्षमताओं के स्वदेशी विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता प्रदान करके भागीदार देशों की क्षमता निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र ने एक लंबा सफर तय किया है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में सबसे आगे हैं।

उन्होंने कहा, 'हाल ही में स्वदेश निर्मित पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण, स्वदेश में विकसित अटैक हेलीकॉप्टर, प्रचंड आदि का समावेशन स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में हमारे प्रयासों में मील का पत्थर है। भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग विदेशी कंपनियों के लिए अपने सहयोग को नए स्तर पर ले जाने के लिए एक आकर्षक और महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, "भारत मित्र आईओआर देशों को विभिन्न प्रकार की मिसाइल प्रणालियों, हल्के लड़ाकू विमानों/हेलीकॉप्टरों, बहुउद्देशीय हल्के परिवहन विमानों, युद्धपोत और गश्ती पोतों, आर्टिलरी गन सिस्टम, टैंकों, रेडार, सैन्य वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और अन्य हथियार प्रणालियों की पूर्ति करने के लिए तैयार है।"

श्री राजनाथ सिंह ने आईओआर देशों से सभी के पारस्परिक लाभ के लिए भारत में सरकार द्वारा बनाए गए अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी प्रणाली का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सही नीतियों और रूपरेखा के साथ भारत एक वैश्विक अनुसंधान और विकास केन्द्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, ''हमारा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी प्रणाली, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में, दुनिया के सबसे बड़े में से एक है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा और एयरोस्पेस

उद्योग में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अब नीतियां और रूपरेखा हैं। हमें अपने साझेदार देशों से बहुत कुछ सीखना है और उनके साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है।"

जलवायु परिवर्तन पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसका समुद्री पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसके प्रभाव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सागर मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि भारत पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्र में बड़ी संख्या में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) आवश्यकताओं में पहला उत्तरदाता रहा है। हालांकि, उन्होंने प्रतिकूल घटनाओं का बेहतर जवाब देने के लिए आईओआर देशों के बीच व्यापक और गहरे आपदा प्रबंधन सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'हम क्षेत्र में नौसेनाओं को तैनात कर रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हम भविष्य में चुनौतियों का सामना करने के लिए 'सेलिंग टुगेदर' से 'ऑपरेटिंग टुगेदर' की ओर बढ़ना चाहते हैं।

अपने स्वागत भाषण में रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने दुनिया भर में सभ्यता की कड़ी के रूप में हिंद महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते वैश्विक एकीकरण का मतलब है कि हिंद महासागर शीर्ष नीतिगत प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा सहयोग को आईओआर में भारत के विविध सहयोग पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण घटक बताया और 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित हिंद प्रशांत महासागर पहल सहित विभिन्न पहलों का उल्लेख किया, जो व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाती हैं। रक्षा सचिव ने दोहराया कि भारत आईओआर क्षेत्र में विकास और निरंतर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर काम करने के लिए तैयार है।

सह नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल एस एन घोरमाडे ने 'लीवरेजिंग टेक्नोलॉजीज एंड होलिस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग- पाथवे टू सेफ एंड सिक्योर ओशियन्स' विषय पर एक व्याख्यान दिया जिसमें समुद्री क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिक सक्षमकर्ता के रूप में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

दूसरे आईओआर+ कॉन्क्लेव में रक्षा उद्योग सहयोग, मरम्मत कार्य के लिए भारतीय शिपयार्डों की उपलब्धता, विमान मरम्मत, पोत डिजाइन और पोत निर्माण, भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच, समुद्री सूचना-साझाकरण, समुद्री निगरानी और सहयोग, एचएडीआर, समुद्री प्रदूषण से निपटने, समुद्री और समुद्री विमानन संसाधनों के नियंत्रित उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं के विकास आदि से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया।

सम्मेलन का आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा किया गया। इस पहल को सभी प्रतिभागी देशों द्वारा बहुत अच्छी तरह लिया गया और अत्यधिक सराहा गया।

एबीबी/डीएस